

वैश्वीकरण, आर्थिक उदारवाद और खुलेपन के बहु-आयामी आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव अब स्पष्ट परिलक्षित होने लगे हैं। इन प्रभावों से शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं है बल्कि कहना यह चाहिए कि इस प्रभाव से शिक्षा के निजी क्षेत्र को बल मिला है और सार्वजनिक शिक्षा तंत्र का हास हुआ है। यह तथ्य सर्व विदित है कि भारत में शिक्षा का निजी क्षेत्र शैक्षिक उत्कृष्टता की गारंटी नहीं देता। इसके इतर शिक्षा में पूंजी-निवेश ने कुछ नयी तरह की प्रवृत्तियों को उभारा है। शिक्षा के समकालीन परिदृश्य को इस संवाद में विश्लेषित और प्रश्नांकित किया गया है।

प्रबन्ध व्यापार शिक्षा या प्रबन्ध शिक्षा का व्यापार ?

□ डॉ. प्रमोद पाठक

एम बी ए यानी प्रबंध शिक्षा आज सर्वाधिक मांग वाली पढ़ाई है। हर तरफ प्रबंध शिक्षा के केन्द्र खुल रहे हैं। शायद एम बी ए की डिग्री या डिप्लोमा को आज की पीढ़ी एक सुखद एवं समृद्धशाली भविष्य का द्वार समझती है। बहुत हद तक यह ठीक भी है। मगर फिर भी यह आवश्यक है कि प्रबंध शिक्षा व्यवस्था का एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन व मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि बहुत से मामलों में प्रबंध व्यापार शिक्षा प्रबंध शिक्षा का व्यापार बन कर रह गया है। ऐसे संस्थान भी काफी संख्या में हैं जो प्रबंध की डिग्री बेचने की दुकान भर हैं। साथ ही यह भी देखने योग्य बात है कि भारतीय प्रबंध शिक्षा भारतीय परिवेश में भारतीय उद्योगों के लिये कितनी सार्थक है? क्या हम सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले, अमेरिकी संस्कृति के पोषक तैयार कर रहे हैं या भारतीय उद्योगों को कुशल व प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में जहां एक ओर इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय उद्योग एवं सेवाएं विश्व स्तरिय हो, वहीं यह भी जरूरी है कि उनका एक अपना निजी स्वरूप भी उभरे। इसके लिये यह नितांत आवश्यक है कि प्रबंधन की विद्या एवं तकनीक की एक मौलिक शैली भी बने। अब तक हम पाश्चात्य मूल्यों एवं विचारधाराओं एवं अवधारणाओं को आयातित करते रहे हैं, किन्तु अपनी ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधकीय परिदृश्य में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं कर पाए। यह ठीक है कि प्रबंधन एक सार्वभौतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह सार्वभौतिकता प्रभावकारी तब होती है जब उसकी सांस्कृतिक ग्राहता हो। आज हम देख रहे हैं कि यहां की प्रबंध शिक्षा में अमेरिकी पद्धति का अंधानुकरण हो गया है।

आज से लगभग 70 वर्ष पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केल्विन कुलिज ने समाचार-पत्रों के संपादकों को संबोधित करते

हुए कहा था कि अमेरिका का धंधा व्यापार है। इस कथन के पीछे छिपी उनकी मंशा साफ है और अमेरिका आज भी एक विश्वसनीय या शायद विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनिया है, जिसका हर कृत्य व्यापार की भावना से प्रेरित होता है। लाभ-हानि की कसौटी पर परखा जाता है। लेकिन इसी संदर्भ में यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि व्यापार प्रबंध (बिजनेस मैनेजमेंट) शिक्षा की उत्पत्ति भी अमेरिका से हुई है, तो यह कहना बहुत गलत नहीं होगा कि आज के अधिकांश व्यापार प्रबंध शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य भी व्यापार ही है। यही वजह है कि सिर्फ पिछले कुछ वर्षों में ही भारत में लगभग पांच सौ से अधिक संस्थान कुकरमुत्तों की तरह उग आए हैं, व्यापार-प्रबंध शिक्षण प्रदान करने के नाम पर जाहिर है, व्यापार शुभ और लाभदायक दोनों ही साबित हो रहा होगा, क्यों न हो? भारत में तो जो चीज बिकती है, वह खूब बिकती है।

यही कारण है कि आज हर दूसरा स्नातक व्यापार-प्रबंध या प्रबंध-शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, बल्कि अब तो स्नातक पूर्व स्तर पर भी प्रबंध शिक्षा उपलब्ध है। बीबीए के नाम से। आज के इस बाजारोन्मुखी माहौल में बाजारोन्मुख शिक्षा की मांग भी तो बढ़ी ही है। इसी मांग को ध्यान में रखकर हर तरफ व्यापार करने के लिए अधिक से अधिक संस्थान खुल रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में करीब 160 संस्थान हैं जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरह तमिलनाडु में 70 और आन्ध्रप्रदेश में 60 ऐसे संस्थान हैं। अन्य प्रदेश जैसे मध्यप्रदेश में भी तेजी से इस तरह के संस्थान खुल रहे हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार देशभर में मान्यता प्राप्त संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या 40,000 थी, जो पूर्णकालिक, अंशकालिक एवं अन्य कार्यक्रम के जरिए भरी गयी। इनके अलावा मुक्त विश्वविद्यालयों के सौजन्य से विभिन्न अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध सीटों की भी काफी बड़ी संख्या है।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या इतने प्रबंध शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए रोजगार या प्रोन्नति के अवसर भी हैं ? और क्या इस तरह के शिक्षण संस्थान सचमुच कुशल प्रबंध शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं ? दोनों ही प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक ही होंगे । जाहिर है, कुछ एक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अधिकांश महज शिक्षा बेचने की दुकानें हैं, वह भी ऐसी दुकानें जो माल की गुणवत्ता की गारंटी नहीं देती। इस तरह की अधिकांश दुकानें निजी व्यवस्था या गैर-सरकारी प्रबंधन के नियंत्रण में चलती हैं, जिन पर सरकारी या अन्य अंकुश का सवाल ही नहीं उठता । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो प्रबंध शिक्षा के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, सिर्फ मान्यता देने तक ही क्रियाशील रहती है । फिर मान्यता देने के लिए जो भी मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, उन पर बहस की काफी गुंजाइश है । नतीजा यह होता है कि इस तरफ की ज्यादातर संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले ठगे जाते हैं ।

मगर इसका अहसास उन्हें तब होता है जब वे अपनी-अपनी उपाधियों के साथ रोजगार के बाजार में अवसर तलाशने निकलते हैं और गैर-प्रबंधकीय रोजगारों से अपने को संतुष्ट करते हैं या समझौता करने को बाध्य होते हैं । मगर प्रबंध शिक्षा के इस व्यवसाय का बाजार बहुत बड़ा है । इनमें प्रवेश पाने पर एक छात्र को औसतन करीब एक लाख रूपए सालाना तक खर्च करना पड़ता है । यानि लगभग चालीस हजार सीटों के लिए कुल राशि लगभग चार सौ करोड़ हुई । यदि प्रवेश के लिए औसतन प्रवेश पत्र इत्यादि का खर्च प्रति विद्यार्थी आठ सौ रूपए मान लिए जाएं तो कुल डेढ़ लाख विद्यार्थियों के लिए यह राशि होगी बारह करोड़ अर्थात एक बहुत बड़ी राशि जिसमें से प्रबंध शिक्षा संस्थान अपना-अपना हिस्सा तलाशते हैं ।

गौर करने वाली बात यह है कि इतने बड़े मसले पर सोचने तक का वक्त किसी के पास नहीं है । न तो प्रवेश परीक्षा की फीस या प्रवेश-पत्रों की कीमत पर कोई नियंत्रण है और न ही प्रवेश और पढ़ाई की फीस पर । मजे की बात यह है कि पाठ्यक्रम पर भी कोई अंकुश नहीं है । सभी संस्थान अपने-अपने ढंग से पढ़ाई का कार्यक्रम चला रहे हैं और प्रबंधक बनाने का दावा कर रहे हैं । न तो कोई मानक है और न ही गुणवत्ता नियंत्रण की कोई प्रक्रिया । यह विडम्बना ही है कि प्रबंध शिक्षा का व्यावसायीकरण महज एक व्यापार बनकर रह गया है ।

कोई भी जो कभी भी कुछ था, आज प्रबंधन पर कुछ न कुछ बोल रहा है और लोग उन्हें सुन रहे हैं । आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए ? क्या सरकार दोषी है? क्या हमारे विश्वविद्यालय जिम्मेवार है ? या उद्योग ? अथवा प्रचार

माध्यम ? शायद सभी ने अपने-अपने ढंग से इस तरह की स्थिति सृजन करने में योगदान दिया है । सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की अमेरिकी अवधारणा को महामंत्र मान लिया और एमबीए शिक्षा का अमेरिकी संस्करण भारत में प्रबंध शिक्षण की दुकानों के जरिए बिकने लगा है। शायद सरकार को यह जानकारी नहीं थी कि प्रबंध शिक्षा में योगदान जापानी सिद्धांतों का आज सबसे ज्यादा योगदान है लेकिन जापान में व्यापार-प्रबंध शिक्षण संस्थान सीमित हैं । कुछ वर्ष पहले तक तो थे ही नहीं । रहा सवाल विश्वविद्यालय का , तो हमारे देश में विश्वविद्यालयों में मौलिक चिंतन कम और सरकारी चिंतन अधिक होता है । लिहाजा इन उच्च शिक्षा के केन्द्रों में सरकारी सोच ही लागू होने लगा और एक के बाद एक प्रबंध शिक्षा विभाग खुलने लगे । हां, ये सरकारी दर पर उपलब्ध सस्ती दुकानें हैं । बाजारोन्मुखी हवा विश्वविद्यालयों में भी बहने लगे हैं । जहां तक उद्योग का सवाल था, तो उनके पास सिर्फ उत्पादन के लिए फुर्सत है, सोचने के लिए नहीं । उन्होंने प्रबंध शिक्षा पर कुछ भी करना-कहना उचित नहीं समझा, बल्कि बहुत से औद्योगिक घरानों ने तो इसे भी एक उद्योग बना दिया । रहे हमारे प्रचार माध्यम तो उनके लिए तो अमेरिकनों येन गतःस पन्था। सुन्दर और चमकीली रंग-बिरंगी तस्वीरों के जरिए प्रबंध शिक्षा का अमेरिकी मॉडल भारत में विकास एवं प्रगति के इंजन के रूप में स्थापित हो गया है । वैसे भी भारत में छपी छपायी बातों पर विश्वास करने का चलन है, विशेष कर अंग्रेजी में छपी बातों पर ।

अब दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं । पहला कि क्या प्रबंध एक शुद्ध अमेरिकी प्रक्रिया है ? दूसरा यह कि क्या प्रबंध शिक्षा के लिए कोई मौलिक, संस्कृति सापेक्ष मॉडल तैयार किया जा सकता है ? यदि हम यह मान लें कि प्रबंधन सिर्फ एक अमेरिकी प्रक्रिया है, तो भी उसे बगैर भारतीय संस्कृति के अनुसार ढाले उसका लाभ नहीं मिल सकता । यही वजह है अमेरिकी पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता देने वाले बड़े एवं ख्याति प्राप्त प्रबंधन संस्थानों के पास किए छात्र विदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में ही काम करना चाहते हैं ।

शायद वे भारतीय उद्योगों में उतने सफल नहीं होंगे । वैसे इस पर एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, लेकिन सच यह है कि प्रबंधन अमेरिकी प्रक्रिया नहीं है। इसे शायद मानवीय प्रक्रिया कहना बेहतर होगा । इसलिए हमारे देश के लिए अमेरिकी मॉडल उपयोगी नहीं साबित होगा । इस लिहाज से दूसरे प्रश्न का उत्तर अधिक महत्वपूर्ण है एक भारतीय प्रबंध शैली का निर्माण करना होगा । शायद खोज करनी होगी । शैली तो पहले से ही है, क्योंकि भारतीय सभ्यता अमेरिकी सभ्यता से ज्यादा पुरानी है, परंतु इससे पहले प्रबंध शिक्षा की आड़ में जो लूट मची है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । ♦